साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 24-30 अक्टूबर, 2022, वर्ष-8, अंक-29

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

खुशखबरी, केंद्र ने रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

सरसों-राई की एमएसपी में 400 रुपए क्विंटल बढ़ी

गेहूं की एमएसपी 2015 से 2125 रुपए प्रति क्विंटल

चना में 105, मसूर की एमएसपी में 500 रुपए की हुई बढ़ोतरी

दिवाली से पहले किसानों को एमएसपी का उपहार

भोपाल। जागत गांव हमार

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह गेहूं के लिए 100 प्रतिशत, मसूर के लिए 85 प्रतिशत, चने के लिए 66 प्रतिशत, जौ के लिए 60 प्रतिशत, और कुसुंभ के लिए 50 प्रतिशत है। सरकार ने रबी फसलों के विपणन सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मसूर के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल और इसके बाद सफेद सरसों व सरसों के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी में पूर्ण रूप से उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कुसुम के लिए 209 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। गेहूं, चना और जौ के लिए क्रमश: 110 रुपए प्रति क्विंटल और 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
विपणन सीजन 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है, जिसका लक्ष्य किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक तय करना है। सफेद सरसों और सरसों के लिए अधिकतम रिटर्न की दर 104 प्रतिशत है।

फसलें	एमएसपी 2022-23	एमएसपी 2023-24
गेहूं	2015	2125
जौ	1635	1735
चना	5230	5335
मसूर	5500	6000
सरसों	5050	5450
कुसुम	5441	5650

सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले

एमएसपी बढ़ाना किसानों को समृद्ध बनाने के दिशा में बड़ा कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023-24 में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के सशक्तिकरण और उनके हित को देखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किसानों को समर्थ बनाने की दिशा में एक और प्रभावशाली कदम है। सशक्त किसान, सशक्त देश के ध्येय की प्राप्ति के इस निर्णय के लिए मप्र के किसानों की ओर से मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया

निर्णय किसानों के कल्याण के साथ ही गांवों को भी समृद्ध बनाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना में भारत यूरिया की सौगात दी है। किसानों को गुणवत्तायक्त यूरिया समान दर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वन नेशन-वन फर्टिलाइजर योजना में देश के हर कोने में एक नाम, एक ब्रांड और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी।

मप्र में 22 लाख किसानों को होगा फायदा

केंद्र सरकार ने किसानों को दीपावली का उपहार देते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन दो हजार 125 रुपए की दर से होगा। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 22 लाख किसानों को मिलेगा, क्योंकि यहां रबी की मुख्य फसल गेहूं है। दो साल पहले पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक उपार्जन करने वाला राज्य बना था। हालांकि, इस बार 46 लाख टन गेहूं का ही उपार्जन हुआ। मध्य प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने वाले देश के प्रमुख राज्यों में आता है। वर्ष 2021 में प्रदेश में उपार्जन 46 लाख टन रह गया। जबकि, 2020 में प्रदेश में एक करोड 29 लाख टन गेहूं का उपार्जन करके रिकॉर्ड बनाया था। केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 110 रुपए की वृद्धि करके दो हजार 125 रुपए करने का लाभ किसानों को मिलेगा। इसी तरह सरसों का समर्थन मूल्य चार सौ रुपए बढ़ाकर पांच हजार 450 रुपए, मसूर का पांच सौ रुपए बढ़ाकर छह हजार और चना का 105 रुपए बढ़ाकर पांच हजार 335 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

फसल बीमा: किसानों को लाभांवित करने में मप्र देश में नंबर वन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के काम में मध्य प्रदेश अव्वल है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के लिए किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है। कोच्चि (केरल) में आठवें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में राज्य सरकार की ओर से कृषि संचालक प्रीति मैथिल नायक ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना का लाभ पात्र किसानों को दिलाने के लिए नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने का काम किया है। किसान अब योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़कर नामांकन करा रहे हैं। प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके कारण संकट के समय में किसानों को काफी सहायता भी मिल रही है। सरकार ने तय किया है कि किसी भी किसान को एक हजार रुपए से कम बीमा राशि नहीं मिलेगी। यदि बीमा दावा कम राशि का बनता है तो सरकार अपनी ओर से अंतर की राशि मिलाकर किसान को दे रही है।

मप्र में आठ लाख किसानों ने कराया पंजीयन

मप्र में धान खरीदी से पहले किसानों का होगा सत्यापन

भोपाल। मध्य प्रदेश में नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार धान का उपार्जन करेगी। आठ लाख किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया है। पात्र किसानों से ही उपार्जन हो, इसके लिए सरकार राजस्व विभाग के कर्मचारियों से यह पता लगवाएगी कि किसान ने धान की बोवनी की थी या नहीं। उसका रकबा (क्षेत्र) कितना था, अनुमानित उत्पादन कितना हो सकता है। इन तथ्यों की पड़ताल के बाद ही किसान से उपज खरीदी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि पिछले साल गेहूं के उपार्जन के समय 44 हजार खसरे ऐसे पाए गए थे, जिनका पंजीयन तो कराया गया पर वहां खेती ही नहीं हो रही थी।

उपार्जन के साथ-साथ कराई जाएगी मिलिंग

सरकार ने धान की मिलिंग उपार्जन के साथ-साथ कराने का निर्णय लिया है। धान की खरीद होने के बाद मिलर को धान आवंटित की जाएगी। प्रति क्विंटल धान पर 67 किलोग्राम चावल बनाकर देना होगा। चावल सीधे भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम को दिया जाएगा। धान के भंडारण के लिए राज्य भंडार गृह निगम ने गोदामों की व्यवस्था कर ली है।

पिछले साल हुए थे 44 हजार फर्जी पंजीयन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व विभाग किसानों के खसरे का सत्यापन करवा रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि किसान जिस खसरे नंबर की भूमि पर धान की बोवनी करना बता रहा है, उसमें वास्तव में धान बोई गई है या नहीं। दरअसल, पिछले साल 33 जिलों में 44 हजार 532 खसरे ऐसे पाए गए थे, जिनका पंजीयन तो हुआ पर जांच में वहां खेती होना ही नहीं पाया गया। कहीं नाला था तो कहीं पठार और कहीं झाड़ियां। ऐसे सभी खसरों को प्रतिबंधित करने के साथ किसानों द्वारा पंजीयन में बताए गए खसरों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए आठ लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें सर्वाधिक कृषक जबलपुर संभाग के हैं। पिछले साल भी लगभग इतने की किसानों का पंजीयन हुआ था।

आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने सरकार ने भेजा प्रस्ताव

प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें वसूलेंगी प्रोफेशनल

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायतों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रही सरकार ने अब ग्राम सभाओं को टैक्स के विकल्प चुनकर अपनी आमदनी बढ़ाने के प्रस्ताव दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पंचायतें अब अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से प्रोफेशनल टैक्स भी वसूल कर सकेंगी। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से टैक्स दे रहा है तो साल भर में वसूला जाने वाला कुल टैक्स 2500 रुपए से अधिक नहीं हो। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वृत्ति कर के लिए जो प्रावधान ग्राम सभा अनिवार्य कर नियम 2001 में करने के लिए कहा गया है, उसके मुताबिक 15 हजार तक की वार्षिक आय वालों से 100 से 200 रुपए, 20 हजार तक की आमदनी वालों से 300 रुपए तक, 30 हजार तक की आमदनी वालों से 400 रुपए, 40 हजार तक की आय पर 600 रुपए, हजार की आय पर 900 और इससे अधिक आय पर 650 से 1400 रुपए तक वृत्ति कर वसूला जा सकता है। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पहले से ही वृत्ति कर दे रहा है तो उससे कुल लगने वाले टैक्स 2500 रुपए में से बकाया राशि टैक्स के रूप में वसूली जाएगी। इसके साथ ही आमदनी में वृद्धि के लिए यह भी कहा गया है कि पंचायतें चाहें तो अपने क्षेत्र में बैलगाड़ी या तांगे चलाने, खींचने या बोझा ढोने के वाहनों में पशुओं का उपयोग करने वाले या कुत्तों और सुअरों को पालने वालों पर टैक्स लगा सकती हैं।

पशु बेचने से चराने तक देना होगा टैक्स

पंचायतों को सराय, धर्मशाला, विश्राम गृह, वधशाला और पडाव स्थलों पर भी टैक्स के विकल्प दिए गए हैं। साथ ही किराए पर चलाई जाने वाली बैलगाड़ी, साइकिल और रिक्शे पर भी टैक्स लगाया जा सकेगा। ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में अब गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गधा, सुंअर बेचने पर टैक्स देना होगा। वहीं हाट बाजार में प्रचार के लिए स्टाल लगाने पर डेढ़ सौ रुपए रोजाना तक शुल्क देना होगा। इसके अलावा अनूसूची 3 की धारा 80 में चारागाह या पशुओं को चराने के बदले भी फीस लेने के लिए प्रावधान किए जा सकेंगे। इस मामले में शर्त यह होगी कि फीस के संग्रहण के लिए कोई पट्टा, सार्वजनिक नीलामी होना जरूरी है। बकरा, बकरी के लिए प्रति पशु 25 से 50 रुपए फीस देना होगा वहीं भैसा, भैस, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, सुअर, गधा, बछड़ा, बछड़ी की बिक्री के लिए पचास से सौ रुपए तक प्रति पशु फीस चुकाना होगा। इन सभी प्रस्तावित संशोधनों को अगले माह से लागू किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान में सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति पर या भवन या संरचना का उपयोग करने के अब शुल्क तय कर दिया गया है। यहां प्रति वर्ग मीटर जगह के लिए रोजाना तीन से पांच रुपए शुल्क देना होगा।

भोपाल। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के ही क्यों हैं? तो जवाब मिलता है, क्योंकि वहां के किसानों को सरकारी खरीद यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद एमएसपी पर होती तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर लाभार्थी किसानों की संख्या पर नजर डालें तो एमएसपी का लाभ पाने वाले किसानों में सबसे ज्यादा तेलंगाना और मध्य

मध्यप्रदेश ने पंजाब-हरियाणा और तेलंगाना को भी किया पीछे

समर्थन मूल्य का लाभ पाने वाले मप्र के किसान अव्वल

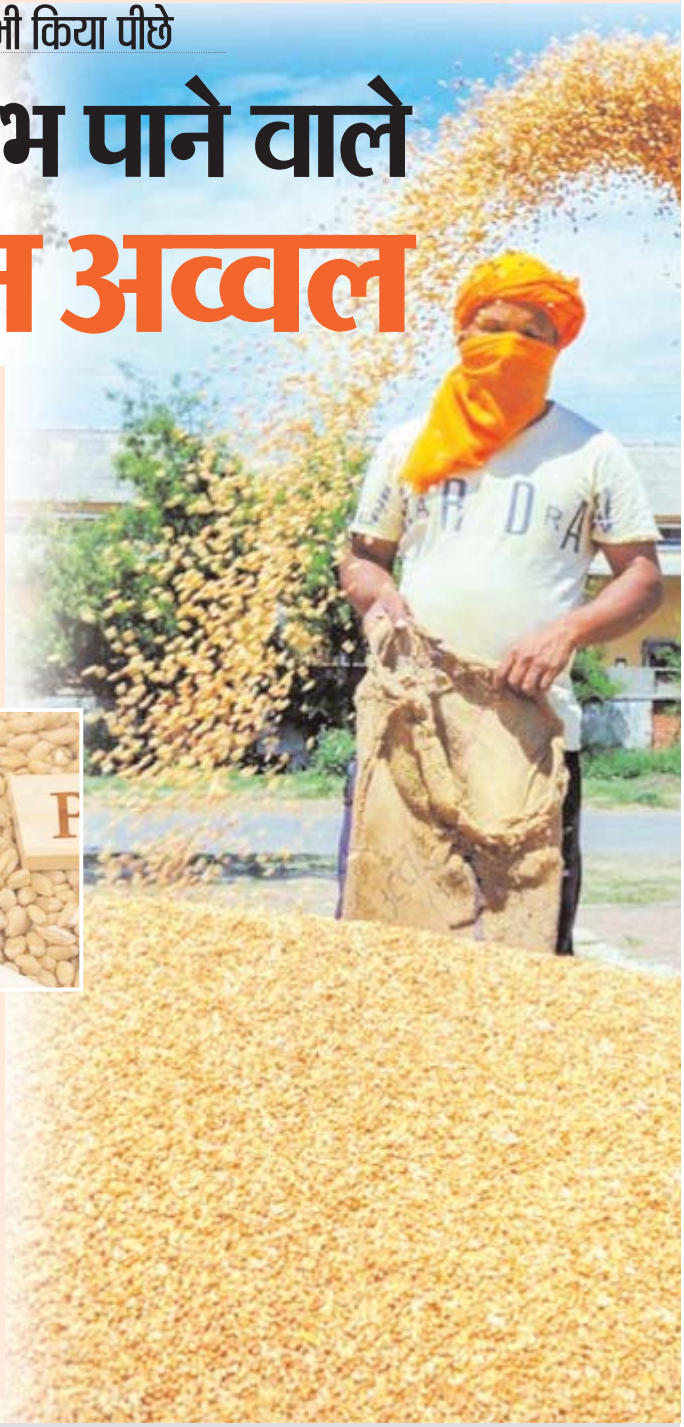

समर्थन पर 23 फसलों की खरीद

फिलहाल इस व्यवस्था के तहत 23 फसलों की खरीद हो रही है, जिनमें गेहूं, धान, ज्वार, कपास, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसलें हैं। सबसे ज्यादा खरीद धान और गेहूं की होती है। नीति आयोग की जनवरी 2016 की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि महज छह फीसदी किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। इन 6 फीसदी किसानों में क्या पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे ज्यादा हैं। पिछले साल 18 सितंबर को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री राव साहेब दादाराव दानवे ने बताया कि खरीफ फसली वर्ष 2019-20 में 9 सितंबर 2020 तक देश के 1.21 करोड़ किसानों से एमससपी पर धान की खरीद हुई जबकि रबी सीजन वर्ष 2020-21 में 43.35 लाख किसानों से एमएसपी पर गेहूं की खरीद की गई। अब यह भी देखते हैं कि इस दौरान किन राज्यों के किसानों से सबसे ज्यादा एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदा गया।

धान खरीदी में तेलंगाना टॉप पर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार खरीफ सीजन 2019-20 में सबसे ज्यादा तेलंगाना के 1,988,630 किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद हुई। इसके बाद दूसरे नंबर हरियाणा रहा जहां के 1,891,622 किसानों ने सरकारी दर पर अपना धान बेचा। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा जहां के 1,838,593 किसानों ने एमएसपी पर धान बेचा, जबकि ओडिशा के 1,161,796 और पंजाब के 1,125,238 किसानों के धान की खरीद एमएसपी पर हुई। मतलब अगर संख्या की बात करें तो एमएसपी पर धान बेचने के मामले में पंजाब के किसान पांचवें नंबर पर रहे। अब गेहूं की भी बात कर लेते हैं। रबी सीजन 2020-21 में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 1,593,793 किसानों ने अपना गेहूं एमएसपी पर बेचा। पंजाब में ऐसे किसानों की संख्या 1,049,982 और हरियाणा में 780,962 रही। उत्तर प्रदेश के 663,810 और राजस्थान के 219,873 किसानों ने गेहूं सरकारी दर बेचा। ये तो एक साल के आंकड़े हैं। 2015-16 से 2019-20 के खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के 16,862,309 किसानों ने अपना धान एमएसपी पर बेचा।

हरियाणा पांचवें नंबर पर रहा

इस मामले में पंजाब (15,851,950) दूसरे, तेलंगाना तीसरे (6,164,444) ओडिशा चौथे (5,150,594) और हरियाणा (4,173,403) पांचवें नंबर पर रहा। इसी तरह 2016-17 से 2020-21 रबी सीजन के बीच सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के 4,785,350 किसानों ने गेहूं सरकारी दर पर बेचा, जबकि पंजाब के 4,456,516 और हरियाणा के 3,730,443

किसानों को गेहूं बेचने पर एमएसपी का लाभ मिला। इस मामले में उत्तर प्रदेश के किसान चौथे (3,450,431) और राजस्थान के किसान (595,123) पांचवें नंबर पर रहे। इन आंकड़ों को देखकर यह तो स्पष्ट है कि एमएसपी का लाभ लेने वाले सबसे ज्यादा किसान पंजाब, हरियाणा को छोड़ दूसरे प्रदेशों के हैं। फिर इस संदर्भ में इन दोनों राज्यों का नाम सबसे आगे क्यों आता है। आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी दर पर धान और गेहूं की सबसे ज्यादा ख़रीद पंजाब और हरियाणा से होती लेकिन धान खरीद के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है। वर्ष 2019-20 तेलंगाना में 76.78 लाख टन धान की पैदावार हुई जिसमें से 97.08 प्रतिशत (74.54 लाख टन) धान की खरीद एमएसपी पर हुई।

देश में धान की खरीद की स्थिति

धान का एमएसपी (ग्रेड ए धान का 1,888 रुपए प्रति क्विंटल और अन्य धान के लिए 1,868 रुपए प्रति क्विंटल) आमतौर पर खुले बाजार की कीमत से अधिक होता है। वहीं गेहूं की एमएसपी 1,975 रुपए प्रति क्विंटल है। बिहार भी धान उत्पादन के मामले शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है, लेकिन सरकारी दर पर खरीद के मामले बहुत पीछे है। बिहार सरकार हर वर्ष 30 लाख मीट्रिक टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य रखती है उसके बावजूद भी सरकार पिछले पांच साल में एक बार भी इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। राज्य में 2014-15 में 19.01 लाख टन, 2015-16 में 18.23 लाख टन 2016-17 में 18.42 लाख टन 2017-18 में 11.84 लाख टन, 2018-19 में 14.16 लाख टन, 2019-20 में 20.01 लाख टन चावल खरीद पाई। और इस साल तो राज्य सरकार ने खरीद की समय सीमा को भी दो महीने कम कर दिया है जबकि इस साल तय लक्ष्य की अपेक्षा 20-22 प्रतिशत ही खरीद हो पाई है।

बढ़ी राज्यों में एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उत्पादन की तुलना में धान खरीदने के मामले में तेलंगाना वर्ष 2019-20 में सबसे आगे रहा। राज्य में उत्पादन की तुलना में 97 प्रतिशत धान की खरीद एमएसपी पर हुई। यह 2017 की अपेक्षा 68 प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी एमएसपी पर धान की खरीद में 467.9 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी गेहूं की खरीद 2017 की अपेक्षा 51 प्रतिशत

प्रदेश के किसान हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। ये व्यवस्था किसानों को खुले बाज़ार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए लागू की गई है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए कि अगर बाजार में फसलों की कीमत गिर भी जाए तब भी सरकार तय एमएसपी पर ही किसानों से उनकी फसल खरीदती है। देशभर में किसी भी फसल की एमएसपी एक ही होती है और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय किया जाता है।

खरीद में राजस्थान चौथे नंबर पर

कुल उत्पादन की 61.28 प्रतिशत खरीद के साथ हरियाणा इस मामले तीसरे नंबर पर, 21.04 प्रतिशत खरीद के साथ राजस्थान चौथे, 11.15 फीसदी खरीद के साथ उत्तर प्रदेश पांचवें नंबर पर रहा। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा और पंजाब में पैदा होनी वाली उपज की खरीद ज्यादा हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में 6 फीसदी किसानों को एमएसपी मिलता है। 94 फीसदी को नहीं मिलता। इन 6 फीसदी में पंजाब और हरियाणा के किसानों की संख्या ज्यादा है। पंजाब में 97 फीसदी के आसपास धान की सरकारी खरीद होती है और 75-80 फीसदी गेहूं की खरीद होती है। बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये बहुत कम है। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उन्होंने सदन में कहा था कि 71 फीसदी लोगों को पता ही नहीं कि एमएसपी क्या है तो, जिन्हें एमएसपी पता ही नहीं, जिन्हें उसका फायदा ही नहीं मिला वो संघर्ष क्यों करेंगे। वे बेचारे खुले बाजार की दया पर आश्रित हैं। अगर सरकारों ने मार्केट का जाल फैलाया होता तो उन्हें भी एमएसपी का फायदा मिलता।

मप्र में 36.20% धान खरीदी

पंजाब में पैदा हुए 118.23 लाख टन धान में से 91.99 प्रतिशत (108.76 लाख टन) और हरियाणा में हुए 48.24 लाख टन धान के उत्पादन में से 89.20 प्रतिशत (43.03 लाख टन) की खरीद सरकारी दर पर हुई। कुल उत्पादन के मुकाबले उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 24.42 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 36.20 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 10.59 प्रतिशत धान की खरीद एमएसपी पर हुई। 2019-20 में धान उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश, देश में सबसे आगे रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे, पंजाब तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे और ओडिशा पांचवें नंबर पर रहा। इस लिस्ट में हरियाणा टॉप-10 में भी नहीं है, लेकिन सरकारी दर पर खरीद के मामले में बहुत आगे है। ये तो रही धान की बात। अब एक नजर गेहूं के उत्पादन और खरीद पर भी डाल लेते हैं। वर्ष 2019-20 में पंजाब में 182.07 लाख टन गेहूं पैदा हुआ जिसमें से 69.83 फीसदी यानी 127.14 लाख टन की खरीद एमएसपी पर हुई। मध्य प्रदेश में उत्पादन तो पंजाब से ज्यादा (185.83 लाख टन) था लेकिन खरीद हुई 69.91 प्रतिशत (129.35 लाख टन) ही हुई।

राज्यों की मंडी व्यवस्था दुरुस्त

पंजाब और हरियाणा की फसल की बिक्री एमएसपी पर सबसे ज्यादा इसलिए भी हो पाती है, क्योंकि इन राज्यों की मंडी व्यवस्था दुरुस्त है। पंजाब में हर 5-6 किमी की दूरी पर कोई न कोई मंडी है। पंजाब में करीब 1,850 खरीद केंद्र, 152 बड़ी मंडियां और 28,000 के आसपास रजिस्टर्ड आढ़ती हैं। इन मंडियों में 2-3 लाख मजदूर ढुलाई, छनाई, पैकिंग आदि का काम करते हैं। ये सब मिलकर करीब 20 लाख किसानों से खरीद करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,477 बड़ी एपीएमसी हैं जबकि 4,843 उप एपीएमसी हैं। कृषि सुधारों के लिए यूपीए सरकार में बनाए गए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक देश में 42,000 मंडियों की जरूरत है। किसान एक बार अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच गया तो उसकी फसल का एमएसपी पर बिकना तय है। लेकिन बाकी राज्यों में यह व्यवस्था कमजोर है। यही कारण है कि यूपी-बिहार से सैकड़ों ट्रक धान औने-पौने दाम में खरीदकर पंजाब में बेचा जाता है।

2020-21 के तहत धान की खरीद हो रही

देश कई राज्यों में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के तहत धान की खरीद हो रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो 18 जनवरी 2021 तक 569.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें अभी पंजाब की हिस्सेदारी 35.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 10.7 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 10.4 प्रतिशत और हरियाणा की हिस्सेदारी 9.8 फीसदी है। धान के दूसरे बड़े उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार में भी धान की खरीद हो रही है, लेकिन ये राज्य इस लिस्ट में भी नहीं हैं।

से ज्यादा हुई है। तेलंगाना में खरीफ सीजन 2019-20 में धान का कुल उत्पादन 76.78 लाख टन में से 74.54 लाख टन (97.08 प्रतिशत) की खरीद एमएसपी पर हुई जो देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। जबकि इससे पहले 2017-18 में कुल उत्पादन 62.62 लाख टन में से 36.18 लाख टन (57.78 प्रतिशत) की ही खरीद एमएसपी पर हुई थी। इस तरह देखें तो पिछले तीन वर्षों में खरीद में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

महाराष्ट्र में भी बढ़ी धान खरीदी

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच तेलंगाना में धान की पैदावार भी काफी बढ़ी है। 2017-18 में धान का उत्पादन जहां 62.62 लाख टन था वहीं 2019-20 में यह बढ़कर 76.78 लाख टन पर पहुंच गया। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी 2017-18 की अपेक्षा 2019-20 में धान की खरीद 467.9 प्रतिशत बढ़ी है। राज्य से खरीफ सीजन 2017-18 में महज 6.55 प्रतिशत धान की खरीद एमएसपी पर हुई थी जबकि 2019-20 में ये आंकड़ा 37.20 प्रतिशत पहुंच गया। इस दौरान उत्पादन में भी (27.31 लाख टन से 37.20 लाख टन) बढ़ोतरी हुई है।

दुनिया भर में 38.5 करोड़ लोगों के बीमार पड़ने की वजह है कीटनाशक

कीटनाशकों का जहर हर साल 11 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। इनमें से करीब 60 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। इतना ही नहीं यह कीटनाशक दुनिया भर में 38.5 करोड़ लोगों के बीमार पड़ने की भी वजह है। यह जानकारी आज जारी नई रिपोर्ट 'पेस्टिसाइड एटलस 2022' में सामने आई है। एटलस के मुताबिक दुनिया भर में इन कीटनाशकों के उपयोग के चलते जो 38.5 करोड़ लोगों के बीमार पड़ने के मामले सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर करीब 25.5 करोड़ एशिया में दर्ज किए गए थे। वहीं अफ्रीका में 10 करोड़ से ज्यादा और यूरोप में 16 लाख मामले सामने आए थे। अकेले दक्षिण एशिया में इसकी वजह से हर साल 18 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, जबकि यह कीटनाशक यहां होने वाली 9,401 लोगों की मौत की वजह है। पता चला है कि इन कीटनाशकों से होने वाली 60 फीसदी मौतें भारत में होती हैं।

1962 में जीवविज्ञानी रेचल कार्सन ने अपनी फेमस पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में कीटनाशक के उपयोग और उसके हानिकारक प्रभावों का वर्णन किया था। इसके बावजूद वर्षों से चलती बहस के बावजूद इन कीटनाशकों का उपयोग आज भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन आज 60 साल बाद भी इन कीटनाशकों के खतरों को दरकिनार करते हुए इनका उपयोग बदस्तूर सिर्फ जारी ही नहीं बल्कि पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट में इन कीटनाशकों के कारण बिहार में हुई 23 बच्चों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि यह बच्चे चावल और आलू की सब्जी खाने के कुछ मिनटों के भीतर ही मर गए थे। यह खाना उन्हें कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार मिडडे मील के तहत दिया गया था। इस भोजन की फोरेंसिक जांच से पता चला था कि इस भोजन को जिस तेल में पकाया गया था उसमें कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस था, जो इन बच्चों की मौत की वजह था। आज न केवल हमारे खेतों बल्कि भोजन, फल, सब्जियों, शहद में भी कीटनाशकों के होने के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं यह जहर हमारे शरीर से लेकर हवा, पानी, पर्यावरण तक में घुल चुका है। सिर्फ इंसान ही क्या इस जहर से दूसरे जीव भी सुरक्षित नहीं है। पता चला है कि इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर खेतों में रहने वाली चिड़ियों और तितलियों की आबादी में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है। पता चला है कि कीटनाशकों के चलते यूरोप में 10 में से एक मधुमक्खी पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। यह केमिकल इंसानों में उनकी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाने से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों की भी वजह हैं। इतना ही नहीं हाल ही में किए एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 64 फीसदी कृषि योग्य भूमि पर कीटनाशक प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद दुनिया भर में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है जो कहीं न कहीं इंसान में बढ़ते लालच को दर्शाता है। रिपोर्ट से पता चला है कि 1990 के बाद से दुनिया भर में कीटनाशकों का उपयोग लगभग दोगुना हो गया है। इतना ही नहीं अनुमान है कि इसका वैश्विक बाजार अगले साल तक 10.8 लाख करोड़ रुपए (13,000 करोड़ डॉलर) तक पहुंच जाएगा। पता चला है कि 1990 से 2017 के बीच जहां दक्षिण अमेरिका में कीटनाशकों के उपयोग में 484 फीसदी की वृद्धि हुई है वहीं एशिया में 97 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

जहर बेच अरबों की फसल काट रही कीटनाशक कंपनियां: वहीं संगठन अनअर्थड और पब्लिक आई द्वारा की गयी संयुक्त जांच से पता चला है कि दुनिया की पांच सबसे बड़ी कीटनाशक बनने वाली कम्पनियां अपनी आय

का करीब एक तिहाई हिस्सा हानिकारक कीटनाशकों को बेच कर कमा रही हैं, जोकि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। इन एग्रोकेमिकल दिग्गजों में बीएएसएफ, बेयर, कोर्टेवा, एफएमसी और सिन्जेंटा शामिल हैं। देखा जाए तो दुनिया भर की जानी-मानी कंपनियां कीटनाशकों के साथ जीएम खेती को भी बढ़ावा दे रही हैं, जो इन कीटनाशकों पर निर्भर हैं। विशेष रूप से यह कंपनियां ऐसे देशों में अपने उत्पाद बेच रही हैं जहां नियम कानून उतने कड़े नहीं हैं। लेकिन देखा जाए तो यह देश जैवविवधता के मामले में विशेष रूप से समृद्ध हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारतीय किसान कीटनाशकों पर प्रति हेक्टेयर 37 फीसदी अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना वो 2002 में जीएम कपास को लाए जाने से पहले करते थे। पता चला है कि यह कम्पनियां अपने अत्यधिक हानिकारक कीटनाशकों (एचएचपी) को ज्यादातर विकासशील देशों में बेच रही हैं। विश्लेषण के अनुसार भारत में इन कम्पनियों द्वारा बेचे गए कुल कीटनाशकों में एचएचपी का हिस्सा करीब 59 फीसदी था। विडम्बना देखिए की यूरोप में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए जिन कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति नहीं है, वो कीटनाशक भी यूरोप जैसे विकसित देशों में न केवल बनाए जा रहें हैं साथ ही उन्हें अन्य देशों को निर्यात भी किया जा रहा है। इस कारोबार में कई यूरोपियन कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसे में इन दोहरे मानदंडों के पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है।

भारत सहित दुनिया के कई अन्य देशों में काफी हद तक कृषि इन कीटनाशकों पर ही निर्भर है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऐसे कीटनाशक शामिल हैं, जिनका अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग मनुष्यों, जानवरों, जैव-विविधता और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।

भारत को ही नहीं दुनिया को भी लेनी होगी सिक्किम से सीख: देखा जाए तो जिम्मेवारी केवल सरकार की ही नहीं है। इस बारे में लोगों और किसानों को भी जागरूक होना होगा। पिछले कुछ दशकों से किसान पैदावार बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में व्यावसायिक कीटनाशकों के उपयोग पर जोर दे रहे हैं। लेकिन वो न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है साथ ही खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

ऐसे में इन हानिकारक कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग पर लगाम कसना जरुरी है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक कीटनाशकों के अलावा कुछ ऐसे कीट हैं जो फसलों में लगने वाले कीटों को रोकने में इन कीटनाशकों से कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी सरकारें उसपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। भारत के लिए एक अच्छा पहलु यह है कि देश में कई राज्य अब कीटनाशकों के उपयोग को बंद करके आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें देश के छोटे से राज्य सिक्किम की बड़ी भूमिका है। यह दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पूरी तरह जैविक खेती को अपना लिया गया है। यह एक ऐसे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां दशकों से कृषि का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर निर्भर है।

प्राकृतिक खेती के लिए वरदान है देसी केंचुआ

भरत लाल पांडेय
उन्नत किसान

मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं देसी केंचुए कृषि विशेषज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित सुभाष पालेकर के मुताबिक जीवामृत के इस्तेमाल से ज़मीन में देसी केंचुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्या आपको पता है केंचुए खेती में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यदि देसी केंचुए नहीं होते तो शायद हरे-भरे जंगल और लहलहाते खेत भी नहीं होते। आज के समय में जब हानिकारक केमिकल वाली खेती की बजाय प्राकृतिक खेती पर ज़ोर दिया जा रहा है, देसी केंचुए की भूमिका और बढ़ जाती है। यह कुदरती तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके इसे अधिक उपजाऊ बनाते हैं।

प्राकृतिक खेती में बहुत मददगार है देसी केंचुआ, जानिए यह अफ्रीकन केंचुए से कितना अलग है?

अक्सर लोगों को लगता है कि वर्मीकंपोस्ट तैयार करने वाले जीव भी केंचुए होते हैं, लेकिन वास्तव में वह देसी केंचुए न होकर अफ्रीकन केंचुए हैं, जिन्हें आयसेनिया फिटिडा कहा जाता है।

देसी केंचुओं की अहमियत: यदि आप पौष्टिक अनाज के लिए कुदरती तरीके से खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि खेत में मिट्टी को अधिक उपजाऊ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए देसी केंचुए बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग वर्मीकंपोस्ट को केंचुए वाली खाद कहते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जीव देसी केंचुआ न होकर अफ्रीकन अर्थवॉर्म यानी आयसेनिया फिटिडा होता है। केंचुए को अंग्रेज़ी में अर्थवॉर्म कहा जाता है। वैसे तो ऑर्गेनिक खेती में वर्मीकंपोस्ट का खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कृषि जानकार देसी केंचुए को ज़्यादा फायदेमंद बताते हैं।

कैसे बढ़ाएं केंचुए की संख्या: महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित सुभाष पालेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, पानी, दलहन, आटा और जंगल की मिट्टी से बने जीवामृत के इस्तेमाल से ज़मीन में केंचुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

देसी केंचुआ बनाम अफ्रीकन केंचुआ: देसी केंचुआ और आयसेनिया फिटिडा अलग-अलग होते हैं। कृषि जानकारों के मुताबिक, देसी केंचुआ में 16 लक्षण होते हैं, जबकि आयसे, निया फिटिडा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं होते हैं। देसी केंचुआ मिट्टी खाता है, जबकि आयसेनिया फिटिडा गोबर खाता है। देसी केंचुआ ज़मीन में अनगिनत छेद करता है जिससे बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जमा होता जाता है। इसके विपरीत, आयसेनिया फिटिडा ज़मीन के ऊपर ही अपना काम करता है। यदि खाना नहीं मिलता है तो देसी केंचुआ खेत से भागता नहीं है, बल्कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, जबकि आयसेनिया फिटिडा खाना न मिलने पर दूसरे खेत में चला जाएगा।

देसी केंचुए की खासियत: देसी केंचुआ ज़मीन में मिट्टी खाते-खाते गहराई तक चला जाता है और ऊपर आने के लिए दूसरा छेद करता है। इससे जमीन में अनगिनत छेद हो जाते हैं। इनकी बदौलत पौधों की जड़ों को गहराई तक पानी और पोषण मिलता रहता है जिससे पौधों का विकास अच्छी तरह होता है। केंचुआ ज़मीन से ऊपर-नीचे करते समय एक तरह पदार्थ छेद की दीवार पर लगा देता है, जिससे वह बंद नहीं होता। इस पदार्थ को वर्मी वॉश कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो जड़ों के लिए आवश्यक हैं। इतना ही नहीं केंचुआ कच्ची चट्टान, रेत कण और मिट्टी खाते-खाते ज़मीन के अंदर जाकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी खा जाता है। यानी केंचुआ फसलों को बीमारी से बचाने में भी मददगार है। केंचुओं को 24 घंटे काम करने के लिए सूक्ष्म पर्यावरण का होना जरूरी है।

सूक्ष्म पर्यावरण क्या है: अब आप सोच रहे होंगे कि यह सूक्ष्म पर्यावरण क्या है, तो आपको बता दें कि दो पौधों के बीच हवा आती जाती रहे और मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, यही सूक्ष्म पर्यावरण है। सूक्ष्म पर्यावरण के निर्माण के लिए खेत में पेड़-पौधों की 2 कतारों के बीच फसलों के अवशेषों को फैलाकर रख दें, बस केंचुआ अपने काम पर लग जाएगा। यदि आप भी प्राकृतिक तरीके से अधिक फसल उगाना चाहते हैं, तो खेत में देसी केंचुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। प्राकृतिक खेती में बहुत मददगार है।

देसी केंचुओं की अहमियत: यदि आप पौष्टिक अनाज के लिए कुदरती तरीके से खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि खेत में मिट्टी को अधिक उपजाऊ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए देसी केंचुए बहुत ज़रूरी हैं। कृषि जानकार देसी केंचुए को ज़्यादा फायदेमंद बताते है।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा है अंतरिक्ष में कचरे का प्रदूषण

पृथ्वी की निचली कक्षा में 10 सेमी से अधिक व्यास वाले 30,000 से अधिक ट्रैक करने योग्य मलबे के टुकड़े और 1 सेमी से इस बात के कई प्रमाण हैं कि ऊपरी वायुमंडल की जलवायु बदल रही है। जबकि निचले स्तरों पर तापमान बढ़ रहा रहा है जिसका असर मध्य और ऊपरी वातावरण पर दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के नए शोध के अनुसार, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2) के बढ़ते स्तर के चलते बहुत अधिक ऊंचाई पर वायु घनत्व में लंबे समय में गिरावट आएगी। इस तरह कम होते घनत्व से 90 से 500 किमी की ऊंचाई के बीच ऊपरी वायुमंडल में परिक्रमा करने वाली वस्तुओं पर खिंचाव कम होगा, जिससे अंतरिक्ष में मलबे का जीवनकाल बढ़ जाएगा और मलबे और उपग्रहों के बीच टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में घनत्व कम होने की वजह से उपग्रहों के अंतरिक्ष में मलबे से टकराने की अधिक आशंका है। जैसे-जैसे लोग नेविगेशन प्रणाली, मोबाइल संचार और पृथ्वी की निगरानी के लिए उपग्रहों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, अगर अरबों डॉलर की लागत वाले उपग्रह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इनके टकराने की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन, अगले 50 वर्षों के लिए ऊपरी वातावरण में जलवायु परिवर्तन का पहला वास्तविक आकलन प्रस्तुत करता है। हालांकि कई अध्ययनों ने निचले और मध्य वातावरण में होने वाले बदलावों की जांच की है, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई वाले परिदृश्यों में शोध बहुत सीमित है। मार्च 2021 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में 2,000 किमी की ऊंचाई पर लगभग 5,000 सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह थे। यह संख्या पिछले दो वर्षों में 50 फीसदी बढ़ गई थी। विभिन्न कंपनियां अगले दशक में हजारों और जोड़ने की योजना बना रही हैं। एक बार इनका काम खत्म होने के बाद, उपग्रह कक्षा में जाते रहते हैं लेकिन वायुमंडलीय खिंचाव के कारण धीरे-धीरे धीमी गति से चलते हैं, जब तक कि वे निचले वातावरण में जलते नहीं हैं, तब तक उनकी कक्षीय ऊंचाई कम हो जाती है। इंटर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबे की समन्वय समिति द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देश के मुताबिक उपग्रह ऑपरेटर यह सुनिश्चित करते हैं कि 25 वर्षों के भीतर निष्क्रिय उपग्रहों को हटा दिया जाए, लेकिन कम वायुमंडलीय घनत्व के योजना और गणना में गलतियां हो रही हैं। निचले वायुमंडल के विपरीत, मध्य और ऊपरी वातावरण ठंडा रहा है। यह उन ऊंचाई पर सेवा मुक्त उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशन से संबंधित मलबे जैसी वस्तुओं पर खींचने के लिए व्यावहारिक प्रभाव के साथ घनत्व में गिरावट की ओर जाता है। कम खिचाव के साथ इन वस्तुओं का जीवनकाल बढ़ जाता है, वस्तुएं अधिक समय तक कक्षा में रहती हैं और सक्रिय उपग्रहों के साथ-साथ अन्य अंतरिक्ष मलबे के साथ टकराने का अधिक खतरा होता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण में एनईआरसी के एक स्वतंत्र शोधकर्ता इंग्रिड कॉनसेन ने 2070 तक ऊपरी वातावरण में बदलावों का अनुकरण करने के लिए 500 किमी ऊंचाई तक पूरे वातावरण के वैश्विक मॉडल का उपयोग किया। उन्होंने अपने अनुमानों की तुलना पिछले 50 वर्षों के आंकड़ों से की और पाया कि भविष्य के मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य के तहत भी अनुमानित औसत ठंडे और ऊपरी वायुमंडल घनत्व में गिरावट अतीत की तुलना में लगभग दोगुनी गति से जारी है।

उद्यानिकी विभाग में हुआ बड़ा सब्सिडी घोटाला

संचालक सहित 15 पर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर कसा शिकंजा

वंदना बृजेश परमार, उज्जैन। जागत गांव हमार

छुट्टा पशु विशेष तौर पर संकर नस्ल की उज्जैन। मंदसौर उद्यानिकी विभाग में वर्ष 2017-18-19 के सत्र में हुए करो ?ें के घोटाले में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है।उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन संचालक सहित उपसंचालक मंदसौर, 7 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं 6 फर्म के संचालक आरोपी बनाए गए हैं। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के अनुसार मुकेश पाटीदार निवासी दलौदा जिला मंदसौर ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जांच मे शिकायत पुष्ट होने के उपरांत जांच लोकायुक्त भोपाल को भेजी गई थी। लोकायुक्त संगठन, भोपाल में अपराध क्रं 214/2022 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)ए, 13(1)बी सहपठित धारा-13(2) तथा भार्दवि की धारा 409, 420, 120बी के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन, भोपाल में अपराध क्र. 214/2022 पंजीबद्ध किया गया है।

इन्हें बनाया गया आरोपी

- शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि विभाग में संचालित योजनायें यथा राज्य योजनायें, एकीकृत बागवानी मिशन योजना यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय औषधी मिशन का क्रियान्वयन किया जाना था। जिनमें कई अनियमितताएं पाई गई।
- जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से पाया गया कि उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले को तुलनात्मक दृष्टि से उपरोक्त योजनाओं के लिए अत्यधिक राशि स्वीकृत की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मंदसौर जिले को कुल 309.4 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं तथा वर्ष 2018-19 में बागवानी यंत्रीकरण के लिए 235.72 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया हैं।
- उप संचालक मनीष चौहान को मंदसौर जिले में दिनांक 12.07.2017 को पदस्थ किया गया तथा राज्य पोषित योजना अंतर्गत घटक यंत्रीकरण में वर्ष 2017-18 में मंदसौर जिले को 14.05 लाख रूपये तथा 2018-19 में 22.76 लाख रूपये बजट आवंटित किया गया। केन्द्र पोषित योजना उप संचालक मंदसौर द्वारा राज्य शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए यंत्र प्रदाता कंपनियों से षड़यंत्र कर अनुदान की राशि को सीधे यंत्र प्रदाता कंपनी के बैंक खाते में अंतरित किया गया।
- हितग्राहियों के चयन में मनमानी की गई तथा एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को यंत्र प्रदाय किये गये। यंत्रों का क्रय एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवेल्पमेंट कॉ.लि. एवं प्रतिष्ठित निर्माता कंपनियों से नहीं किया गया।
- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के आदेश अंतर्गत स्पष्ट था कि एकीकृत बागवानी मिशन योजना यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राट्रीय औषधी मिशन का क्रियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से करने के निर्देश थे, जो नहीं किया गया। इसके साथ ही कार्य का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया।
- तत्का. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के आदेश से राज्य शासन के अनुमोदन के बिना कृषक अंश का भुगतान आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित कंपनी/फर्म के खाते में भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी जबकि केन्द्र प्रवर्तित योजना में कोई भी संशोधन राज्य सरकार ही करने को अधिकृत हैं।
- कंपनियों के मैनेजर/संचालकों ने अपने कथनों में स्वीकार किया कि निर्धारित यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत किसानों से नगद प्राप्त किया तथा उसकी रसीद भी किसानों को दी गयी।
- किसानों को निर्धारित यंत्र पॉवर ट्रिलर की बिक्री न करते हुए रोटरी ट्रिलर की बिक्री की गयी, जो पावर ट्रिलर से काफी कम कीमत की होती हैं। पॉवर ट्रिलर की न्यूनतम कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये होती हैं, वही रोटरी ट्रिलर की कीमत लगभग 60,000 रुपये होती हैं। इस संबंध में बागवानी मिशन के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों (अप्रैल 2014) का पालन भी नहीं किया गया।
- उद्यानिकी विभाग मंदसौर के अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से जिला स्तरीय तकनीकी समिति से भौतिक सत्यापन कराने के बजाय विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी स्तर के अधिकारियों से ही भौतिक सत्यापन कराया गया।
- यंत्र प्रदाता कंपनियों द्वारा किसानों को यंत्र वितरण करते समय अतिरिक्त राशि भी वसूल की गयी तथा योजना की मंशा के विपरीत यंत्र प्रदाता कंपनियों ने ही हितग्राहियों का चयन स्वयं कर लिया एव उनसे नगद राशि लेकर शेष अनुदान राशि के बिल उद्यानिकी विभाग में लगाकर अनुदान राशि स्वयं की फर्म के खातों में प्राप्त कर ली।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनार के पौधों एवं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के भुगतान में भी अनियमितताएं पायी गयी हैं। इन योजनाओं का पैसा भी डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही कृषकों के बैंक खातों में भेजना था जो नहीं करते हुए सीधे पौधा वितरण कंपनी एवं ड्रिप इरीगेशन संयंत्र कंपनी को भुगतान कर दिया गया। योजनांतर्गत प्रदान किये गये अनार के सभी पौधे वर्ष 2017-18 में गर्मी पड़ने से सूख गये तथा किसानों को कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओ की नीति का भी पालन नहीं किया तथा यंत्र प्रदाता कंपनी द्वारा किसानों से सीधे भुगतान प्राप्त किया। -योजना की शर्तों में द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही अनुदान राशि का भुगतान करना था परंतु राशि पौधा वितरीत करने के बाद ही कंपनियों को प्रदान कर दी गयी। संरक्षित खेती योजना अंतर्गत पॉली हाउस/शेडनेट हाउस/वॉक इन टनल से संबंधित योजना के दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया। हितग्राहियों के खातों में अनुदान राशि का भुगतान न करते हुए किसान एग्रोटेक एवं अन्य कंपनियों के खातों में भुगतान कर दिया। उद्यानिकी विभाग जिला मंदसौर के अधिकारियों एवं कृषि यंत्र प्रदाता कंपनियों तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनार पौधा तथा ड्रिप इरीगेशन कंपनियों द्वारा आपसी षड्यन्त्र कर उद्यानिकी विभाग मंदसौर में संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन में नियम विरूद्ध तरीके से अमानक स्तर के कषि यंत्रों की कथित खरीदी तथा यंत्र प्रदाता कंपनियों एवं अनार पौधा एवं ड्रिप इरीगेशन वितरण कंपनियों को नियम विरूद्ध तरीके से कृषक अनुदान राशि का भुगतान कर शासन को आर्थिक हानि कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ है।

इन्हें बनाया गया आरोपी

- सत्यानंद, तत्कालीन संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल
- मनीष चौहान, उप संचालक, उद्यानिकी विभाग मंदसौर
- राजेश जाटव, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं सह प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड मल्हारगढ, जिला मंदसौर,
- पप्पूलाल पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मंदसौर
- बनवारी वर्मा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड़, सीतामऊ, जिला मंदसौर
- उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड गरोठ, जिला मंदसौर,
- सत्यम मण्डलोई, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड़ भानपुरा, जिला मंदसौर
- सुरेशसिंह धाकड़, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मंदसौर,
- दिनेश पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मंदसौर
- प्रोप्राइटर- सुरेश मणिभाई पटेल, फर्म- गणेश ट्रेडिंग कंपनी, जबलपुर, निवासी- ग्राम आमोद, तहसील पिटलाद, जिला आणंद गुजरात
- प्रोप्राइटर प्रवीण भाई मूलजी,फर्म-छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस निहार अस्पताल के सामने, धम्धा रोड़, जेवरा सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ, निवासी- कातुलबोर्ड वार्ड नं. 59, मकान नंबर16/90 हरिनगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़
- प्रोप्राइटर- मितुलभाई पिता प्रवीणभाई पटेल, फर्म-जे.एम. इंटरप्राईजेस, हरिनगर दुर्ग, छत्तीसगढ़,
- मिहिर पण्ड्या , डायरेक्टर, एबीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी, प्रा.लि., प्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात,
- मंगलन शिवदासन, डायरेक्टर, एवीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी, प्रा.लि., प्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात
- शिवसिंह मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट नंबर 75-86 सेक्टर सेकेण्ड पीथमपुर धार

ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से उद्यानिकी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा

भोपाल। नर्सरियों के विकास और माली ट्रेनिंग सहित उद्यानिकी विभाग की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समन्वय करेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और उद्यानिकी विभाग के समन्वय के संबंध में अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बैठक की। राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों के विकास और माली प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास विभाग सहयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उद्यानिकी के क्षेत्र में दोनों विभाग के समन्वय से किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए संयुक्त रूप से कार्य-योजना तैयार करें। बैठक में उद्यानिकी विभाग की 50 नर्सरी के विकास और माली ट्रेनिंग कार्यक्रम को ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से करने का निर्णय लिया गया। संचालक उद्यानिकी निधि निवेदिता, संयुक्त आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास एमएल त्यागी और अन्य अधिकारी

धान की फसल पर ब्लास्ट रोग प्रबंधन पर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित

ग्वालियर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर द्वारा भितरवार ब्लॉक के ग्राम निकोड़ी में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। जिले मे खरीफ फसलों में धान की खेती व्यापक पैमाने पर सिचित क्षेत्रों में की जाती है। अनियमित तथा अधिक वर्षा के कारण असमती किस्मों में रोगों का प्रकोप अधिक होता है। धान की फसल को ब्लास्ट (प्रध्वस) रोग से बचाने के लिये कृषि विज्ञान केंद्र, ग्वालियर द्वारा कृषक प्रक्षेत्रों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन डाले गए जिसने कृषकों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन के साथ फफूंदनाशक के प्रयोग पर जागठक किया। कृषकों के द्वारा जानकारी के अभाव में रोग संवेदनशीत जिस्म पूसा 1121 का प्रयोग किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविन्दर कौर ने बता कि भारतीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली हमा उच्चत शील तथा रोग प्रतिरोधी किनो का विकास किया जा रहा है। इनमें से पूसा 1718 वैक्टीरियल झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म है तथा अधिक उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि अनुकूल मौसम में रोग के लक्षण दिखई देने पर कंपूनाशक का प्रयोग करना चाहिये जिससे उत्पादन सही प्राप्त हो सके। इस कायक्रम में केन्द्र की वैज्ञानिक डॉ. सुरुचि सोनी का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में 25 कृषकों ने आज लिया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, ग्वालियर के प्रमुख डॉ. राज सिंह शवाह के मार्गदर्शन में किया गया।

अब देशभर में खत्म होगा संकट, मिलेगी राहत

खाद के बंद कारखानों को शुरू कर रही सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

बिहार के बरौनी प्लांट से यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। बरौनी प्लांट से यूरिया उत्पादन शुरू होने से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पं बंगाल सहित देश के कई राज्यों में यूरिया की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट को मोदी सरकार ने दोबारा से निर्माण कराया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी प्लांट सरकार द्वारा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक पहल का हिस्सा है। यूरिया क्षेत्र में घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपये के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है। इस प्लांट की 12 ।7 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता होगी।

देश में स्वदेशी यूरिया का होगा उत्पादन

एचयूआरएल के तीनों संयंत्रों के शुरू होने से देश में 38.1 एलएमटीपीए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। यह भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में से एक है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी। यह परियोजना न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़कों, रेलवे, सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। यूरिया का उत्पादन, किसान, बरौनी प्लांट, यूरिया का उत्पादन शुरू, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पं बंगाल, किसानों को बहुत होगा फायदा, हिंदुस्तान उर्वरक, रसायन लिमिटेड, मोदी सरकारकेंद्र सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपए के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है।

बरौनी खाद कारखाना फिर हुआ शुरू

एचयूआरएल 15 जून, 2016 से अधिकृत एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और एफसीआईएल/एचएफसीएल के साथ मिलकर गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को अनुमानित रूप से पुनर्जीवित करने के लिए अधिकृत किया गया है। मोदी सरकार ने इस कार्य के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

इन राज्यों में यूरिया की मांग होगी पूरी

एचयूआरएल संयंत्रों में डीसीएस (डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम), ईएसडी (आपातकालीन शटडाउन सिस्टम) और पर्यावरण निगरानी प्रणाली आदि से लैस अत्याधुनिक ब्लास्ट प्रूफ कंट्रोल रूम जैसी कई अनूठी विशेषताएं हैं। इसमें 65 मीटर लंबाई और 2 मीटर ऊंचाई वाला भारत का पहला एयर ऑपरेटेड बुलेट प्रूफ रबर डैम भी है। इन संयंत्रों में कोई बाहरी अपशिष्ट जल निपटान नहीं है। सिस्टम अत्यधिक प्रेरित, समर्पित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित ऑपरेटरों द्वारा संचालित होते हैं। यह सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में यूरिया की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दुनिया की सर्वोत्तम तकनीकों को एकीकृत करती है। यूरिया आपूर्ति के अलावा यह परियोजना विनिर्माण इकाई के आसपास लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों/विक्रेताओं को विकसित करने में भी मदद करेगी। हब के आसपास बहुत सारी उद्यमिता गतिविधियां होंगी और इससे रोजगार सृजन को और बढ़ावा मिलेगा। संयंत्रों के संचालन से यूरिया उर्वरक में देश को आत्मनिर्भर बनाने, आयात में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की बचत और उर्वरक में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उल्लेखनीय है कि एचयूआरएल का गोरखपुर संयंत्र दिसंबर, 2021 में पहले ही चालू हो चुका है और सिंदरी संयंत्र शीघ्र ही चालू होने की संभावना है।

किसान बेकार और बंजर जमीन से भी अब कमाएं लाखों

भोपाल। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी अपने-अपने स्तर पर कई बेहतर योजनाओं पर कार्य करती रहती हैं। ताकि देश के किसान भाइयों को सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में सरकार अब कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को एक साथ जोड़ने पर कार्य कर रही हैं। बता दें कि कृषि क्षेत्र में सोलर पंप व सोलर पैनल की योजनाएं भी बनाई हुई है। इन योजनाओं के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत सरकार ने खाली और बेकार पड़ी जमीन और बंजर खेतों के लिए सौर ऊर्जा आजीविका योजना बनाई है। इस योजना को राज्य में 17 अक्टूबर 2022 को राज्य ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लांच किया है।

आजीविका योजना का उद्देश्य

- सरकार की इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बंजर-बेकार जमीनें के मालिक, किसानों, विकासकर्ता और साथ ही संबंधित डिस्कॉम या फिर कंपनी के साथ जोड़ना है।
- इस योजना से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाली कंपनियां सीधे किसानों से जुड़ सकेंगी।
- इसकी मदद से कंपनियों को सरलता से जमीन लीज पर उपलब्ध होंगी।
- किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाना।
- हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करना।

ऐसे लगवाएं सौर ऊर्जा संयंत्र

अगर आप भी अपनी बंजर व बेकार पड़ी खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। इसके लिए आपको पीएम कुसुम योजना के तहत की 30 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा।

उत्कृष्ट कार्य शिक्षा, शोध एवं प्रसार के लिए दिया गया सम्मान

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र रीवा मप्र के वैज्ञानिकों डॉ. अखिलेश कुमार पौध संरक्षण वैज्ञानिक एवम कीट विज्ञान विभाग प्रमुख, कृषि महाविद्यालय, रीवा को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड एवं डॉ. स्मिता सिंह सस्य वैज्ञानिक को यंग साइंटिस्ट अवार्ड सोसायटी कृषि विज्ञान, कोलकाता के सचिव डॉ. मनोज शर्मा एवम राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, उज्जैन के वैज्ञानिक डॉ. डीएस तोमर, आयोजक सचिव के मार्गदर्शन में आयोजित 17 से 19 अक्टूबर 2022 राष्ट्रीय कांफ्रेंस में मुख्य अतिथि डॉ. एनएस राठौड़, पूर्व उप महानिदेशक शिक्षा आईसीएआर एवम पूर्व कुलपति एमपी यूएटी, उदयपुर, राजस्थान ने उनके द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य शिक्षा, शोध एवं प्रसार के लिए दिया। इस अवसर पर पूर्व कुलपति प्रो. पीके शर्मा, एसके यूए एसटी, जम्मू, अशोक दलवई आईएएस, डॉ. पी कुमारवेल, डॉ. मनोज कुमार शर्मा, डॉ. एनसी साहू, डॉ. डीएस तोमर उपस्थित रहे और पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभ कामनाएं दी।

राष्ट्रीय कांफ्रेंस उज्जैन में केवीके के वैज्ञानिकों को मिला पुरस्कार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति प्रो. पीके बिसेन एवं संचालक विस्तार सेवाएं प्रो. दिनकर प्रसाद शर्मा एवं अटारी के निदेशक डॉ. एसआर के सिंह, कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठाता प्रो. एसके पयासी, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख प्रो. एके पांडेय के साथ-साथ प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों में डॉ. एस के त्रिपाठी, डॉ. एके जैन, डॉ. आरके तिवारी, डॉ. आरपी जोशी, डॉ. टीके सिंह, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. सीजे सिंह, डॉ. संजय सिंह, डॉ. केसी सिंह, डॉ. बीके तिवारी, संदीप शर्मा, एमके मिश्र, डॉ. राधा सिंह, अनुपमा अग्रवाल, सुधीर सिंह, एके पटेल, डॉ. प्रदीप मिश्रा के साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न इकाइयों में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मप्र में पीएमवाणी वाईफाई नेटवर्क इन्टरफेस योजना प्रारंभ

नीमच। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल उचित मूल्य दुकानों पर नेट कनेक्टिविटी एवं वाई-फाई की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएमवाणी की कार्यशाला का आयोजन गत दिवस जिला पंचायत में सम्पन्न हुआ। जिसमे डाटा एयर कंपनी के पीएम वाणी कार्यक्रम के डायरेक्टर लोकेन्द्र सिंह राठौर कम्पनी के मप्र प्रभारी रविन्द्र पाटीदार एवं मनीष पाटीदार ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जावद जितेन्द्र नागरखाद्य निरिक्षक एवं जिले के सभी सेल्समेन उपस्थित थे। अब सरकारी राशन की

दुकानों पर अब अनाज, आटा,दाल के साथ इंटरनेट डाटा भी मिलेगा। कंपनी के एमडी लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया ने बताया, कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की पीएम वाणी योजनान्तर्गत नीमच जिले में अब पब्लिक डाटा ऑफिस खोले जाएंगे। इससे राशन डीलर डाटा एयर इंदौर कार्यालय से संपर्क कर पीडीओ बनाकर ग्राहकों को सस्ते दर पर इंटरनेट डाटा बेच पाएंगे। इस के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई टेक्स (ऐजीआर) देना पड़ेगा। केवल अपनी दुकान पर इंटरनेट कनेक्शन लेना है, जो किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी से प्राप्त कर सकता है, जो न्यूनतम 300 एमबीपीएस का हो। केंद्र सरकार की योजना के तहत पब्लिक डाटा ऑफिस से लोगों को डाटा मिलेगा।

धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभाग के द्वारा अनुदान नियमों में किया गया बदलाव

अब किसानों को इन फर्म से मिलेगा कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में किसान भाइयों ने खेत में रबी सीजन की फसलों की बुवाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को बेहतरीन और मजबूत कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जानते हैं बाजार में खेती-किसानी से जुड़े कृषि यंत्र बेहद महंगे आते हैं। इसी क्रम में किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना भी उपलब्ध करवाती है। आपको बता दें कि अबतक देश के किसान सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना से कहीं से भी यंत्र खरीदकर अनुदान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन सरकार ने अब इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। आइए इस बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं कि अब किसानों को खेती-बाड़ी संबंधित कृषि यंत्रों पर कैसे अनुदान की राशि प्राप्त होगी।

ऐसे मिलेंगी कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि

जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि अब किसान पहले की तरह कृषि यंत्र कहीं से भी खरीदकर अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर किसान कृषि यंत्र पर अनुदान की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसानों उन्हीं कंपनी से यंत्र खरीदने होंगे, जिसका कृषि विभाग से पंजीकरण सही तरीके से हुआ हो। अगर वह किसी अन्य फर्म से यंत्र को खरीदते हैं, तो उन किसानों को अनुदान की राशि से वंचित कर दिया जाएगा। बता दें कि विभाग प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएं जाते हैं।

ऐसे लेते थे अनुदान की राशि

किसान पहले अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहरी जिलों से कृषि यंत्र खरीदते थे और फिर बाद में बिल लगाकर भुगतान की राशि प्राप्त करते थे। किसानों के इस तरीके से ऐसे कई फर्जीवाड़े होते थे। पिछले वर्ष कृषि यंत्रों पर कई फर्जीवाड़े पकड़े भी गए थे। जिसमें किसानों के द्वारा गलत बिल लगाकर सरकार से अधिक राशि लेने की कोशिश की है। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए कृषि विभाग के द्वारा अनुदान नियमों में बदलाव किया गया है। किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कृषि यंत्र खरीदते समय स्वयं पुष्टि करनी होगी। इसके लिए किसी दूसरे की पुष्टि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की घोषणा

देश में एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ाने एक्सी लरेटर प्रोग्राम होगा शुरू

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि स्टार्टअप के लिए बड़ी नीतिगत पहल करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिवस पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पूसा मेला ग्राउंड, दिल्ली में दूसरे दिन आयोजित एग्री स्टार्टअप कांफ्रेंस में तोमर ने बताया कि कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। एग्री स्टार्टअप्स की सफल पहलों को आगे बढ़ाने व उनके लोकव्यापीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बड़ी संख्या में उपस्थित एग्री स्टार्टअप प्रतिनिधियों के बीच केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित एजेंसियों जैसे डेयर, डीपीआईआईटी, कृषि इनक्यूबेटर व ज्ञान भागीदारों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, के शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, कृषि मंत्रालय में कृषि स्टार्टअप के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अलग डिवीजन बनाया जाएगा। प्रमाणन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ एग्री स्टार्टअप के लिए आवश्यक सभी

लिंकेज की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सेल भी बनाया जाएगा। तोमर ने बताया कि एग्री स्टार्टअप द्वारा विकसित उत्पादों की, बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नाम व नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा। सभी कृषि स्टार्टअप के लिए एक डेटाबेस तैयार करने और उनके विकास की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास होगा। तोमर ने कहा कि 8 साल पहले मात्र 80-100 कृषि स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या दो हजार से भी अधिक है, जिनमें से सैकड़ों को कृषि मंत्रालय की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार का इन्हें 10 हजार करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व शोभा करंदलाजे भी उपस्थित थी। कृषि सचिव मनोज अहूजा व आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने भी संबोधित किया। प्रारंभ में, देशभर से आए सैकड़ों स्टार्टअप के अनेक प्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव मंत्रीगण के समक्ष रखे। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री तोमर ने दोनों राज्यमंत्रियों के साथ विभिन्न स्टाल का अवलोकन कर स्टार्टअप से जानकारी ली।

मध्य प्रदेश में 6 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए

धार। जागत गांव हमार

इफको ने मध्य प्रदेश में 6 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए ङ्क इफको द्वारा मध्य प्रदेश में 6 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का निर्माण किया गया जिसके तहत किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, खेती उपयोगी कृषि रसायन एवं अन्य कृषि आदान की बिक्री की जाएगी।

किसान समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे किसानों को खाद बीज आदान के साथ अन्य योजनाओं का लाभ जैसे मिट्टी परीक्षण, पानी की जांच के साथ फसल में संतुलित मात्रा में खाद की जानकारी दी जाएगी, इसके साथ कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा खाता खसरा नकल आधार कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ देना है। उसके साथ कस्टम हायरिंग केंद्र का काउंटर भी स्थापित किया गया यह सभी योजनाएं एक ही छत के नीचे संचालित होकर किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने योगदान देगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कालीचरण सोनवानीया, उपाध्यक्ष नगर पालिका धार, अतिथि ज्ञान सिंह मोहनिया उप संचालक कृषि विभाग धार एवं परियोजना संचालक आत्मा व संगीता चौहान सहायक संचालक कृषि विभाग धार एवं विकास चौरसिया क्षेत्र अधिकारी इफको उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन इफको बाजार अधिकारी हरपाल सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने सभी किसानों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र की जानकारी दी। उप संचालक कृषि मोहनिया ने इसे किसानों के लिए वरदान बताया और कहा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र द्वारा पूरे जिले के किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को खाद बीज के साथ मिट्टी परीक्षण की भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। कृषि विकास अधिकारी मुकुल सत्यार्थी जी द्वारा केंद्र से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बताया गया, विकास चौरसिया द्वारा नैनो यूरिया की तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी गई और बताया गया की प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र धार जिले में स्थापित होने से मंडी में आए किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा, कार्यक्रम का आभार अंकित मुकाती इफको द्वारा माना गया।

विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन

पन्ना। कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना द्वारा विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत दिनांक 02 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विशेष अभियान अंतर्गत कार्यालय एवं परिसर की सफाई के साथ आसपास के गांवों में स्वच्छता जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना के अंगीकृत ग्रामों में स्वच्छता अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन विशेष रूप से

केंचुआ खाद निर्माण हेतु कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंचुआ खाद के माध्यम से कृषक अपने खेत का अवशेष से पोषक तत्व युक्त केंचुआ खाद बना सकते हैं साथ ही डिकम्पोजर के प्रयोग से फसल अवशेष को शीघ्र सरकार उससे भी खाद बना सकते हैं।

अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ द्वारा ग्राम कुंजवन का भ्रमण

पन्ना। डॉ. वी.के. सिंह, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़, डॉ. एस.पी. सिंह एवं डॉ. रूद्रसेन सिंह द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षणरत 28 कृषि स्नातक छात्रों के प्रगति कार्य के निरीक्षण हेतु ग्राम कुंजवन का भ्रमण किया गया। डॉ. सिंह ने छात्रों को रावे का उद्देश्य एवं इसके सफल क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने छात्रों को सलाह दिया कि योनाबद्ध तरीके से कार्ययोजना तैयार कर पूर्व निष्ठा के साथ मेहनत करें ताकि भविष्य में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। उन्होंने कृषकों के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया एवं कृषकों से विस्तार से चर्चा किया। कृषि महाविद्यालय टीकमग ? के रावे प्रभारी

डॉ. एस.पी. सिंह ने छात्रों को नियमित रूप से प्रक्षेत्र भ्रमण एवं अन्य रावे संबंधित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। केन्द्र के प्रभारी डॉ. पी.एन. त्रिपाठी ने छात्रों को कृषि से संबंधित तकनीकी अनुभव हेतु कृषक प्रक्षेत्र पर विभिन्न कार्यों में सहभागिता हेतु सलाह दिया। केन्द्र के रावे प्रभारी डॉ. आर.के. जायसवाल ने रावे छात्रों को प्रतिदिन की गतिविधियों को डायरी में लेखन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। श्री रितेश बागोरा ने छात्रों को मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताया। अधिष्ठा महोदय एवं उनकी टीम द्वारा केन्द्र के खरीफ मौसम में प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रक्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं प्रक्षेत्र प्रभारी डॉ. रणविजय प्रताप सिंह ने प्रक्षेत्र की वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराया। भ्रमण के दौरान केन्द्र के वैज्ञानिक, कर्मचारी, प्रगतिशील कृषक एवं रावे छात्रों सहित 32 लोग उपस्थित रहे।

किसानों को राहत
पीएम-किसान निधि 16,000 करोड़ जारी

मोदी ने किया सम्मेलन में पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ

देश में अब एक राष्ट्र-एक उर्वरक

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन-2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना- एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर एक ई-पत्रिका इंडियन एज का भी विमोचन किया। मोदी ने कहा कि आज 600 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। ये केंद्र न केवल उर्वरक के लिए बिक्री केंद्र हैं बल्कि देश के किसानों के साथ एक घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला एक तंत्र हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज, एक राष्ट्र एक उर्वरक के रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की गई है।

यूरिया की नहीं हो रही कालाबाजारी- 2014 से पहले के उस समय को याद करते हुए जब किसानों को संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र और यूरिया की कालाबाजारी से जूझना पड़ता था, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों को अपना उचित हक जताने के लिए भी डंडों का आघात सहना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यूरिया पर 100 प्रतिशत नीम का लेप लगाकर उसकी कालाबाजारी को रोका है। हमने देश की उन 6 सबसे बड़ी यूरिया फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की, जो वर्षों से बंद पड़ी थीं।

भारत ब्रांड नाम से उपलब्ध होगा यूरिया

प्रधानमंत्री ने भारत की उर्वरक सुधार की कहानी में दो नए उपायों का उल्लेख किया। सबसे पहले देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों' के रूप में विकसित करने का एक अभियान आज शुरू किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी परीक्षण भी करा सकते हैं और कृषि तकनीकों के बारे में उपयोगी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, 'एक राष्ट्र, एक उर्वरक' से किसान को खाद की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता को लेकर फैली हर तरह की भ्रांति से मुक्ति मिलने वाली है। अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा और यह ब्रांड 'भारत' है। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम के तहत ही उपलब्ध होगा।

भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तरल नैनो यूरिया उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम लागत में अधिक उत्पादन करने का माध्यम है। इसके लाभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया से भरी एक बोरी का स्थान अब नैनो यूरिया की एक बोतल ले सकती है। इससे यूरिया की परिवहन लागत में भी काफी कमी आएगी।

1700 नई किस्मों के बीज उपलब्ध

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कृषि में नई प्रणालियां सृजित करनी होंगी, खुले दिमाग से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों को भी अपनाना होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि में वैज्ञानिक विधियों को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। अभी तक 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए भी वैज्ञानिक प्रयास जारी हैं। पिछले 7-8 वर्षों के दौरान किसानों को बदली हुई जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल लगभग 1700 नई किस्मों के बीज उपलब्ध कराए गए हैं।

पाम का लाभ उठाने का आग्रह

प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों से मिशन ऑयल पाम का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया, जो खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर भारत खाद्य तेलों की खपत को कम कर सकता है। हमारे किसान इस क्षेत्र में बहुत सक्षम हैं। दलहन उत्पादन के संबंध में 2015 में अपने आह्वान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने दलहन उत्पादन में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रसन्नता व्यक्त की और किसानों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में हम कृषि को बेहद आकर्षक और समृद्ध बनाएंगे।

देश में अनेक हब बनाए जा रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां जो पारंपरिक मोटा अनाज-बाजरा होता है, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब बनाए जा रहे हैं। अगले वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने सिंचाई के लिए अंधाधुंध मात्रा में पानी का उपयोग करने के बारे में सचेत किया और 'प्रति बूंद, अधिक फसल', सूक्ष्म सिंचाई और ड्रिप सिंचाई की दिशा में सरकार के प्रयासों को दोहराया। पिछले 7-8 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने का एक अहम रास्ता प्रदान करता है। इसके लिए भी पूरे देशभर में आज हम काफी जागरूकता का अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ यूपी, उत्तराखंड में बड़े स्तर पर किसान काम कर रहे हैं। गुजरात में तो जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि है।

मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय का होगा विस्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय का होगा विस्तार। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा गत दिनों प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अधीन 163 नवीन पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय का पुनर्गठन कृषि के वर्तमान परिस्थितियों में यंत्रीकरण के महत्व को देखते हुए किया गया है। अभी तक इस संचालनालय के प्रदेश के 32 जिलों में जिला कार्यालय एवं छह संभागों में संभागीय कार्यालय कार्यरत थे। पुनर्गठन के उपरांत संचालनालय की गतिविधियां प्रदेश के सभी 52 जिलो में विस्तारित हो जाएगी। उज्जैन एवं नर्मदापुरम में भी नए संभागीय कार्यालय प्रारंभ होगें। संचालनालय को भी 3 संयुक्त संचालक, 5 कृषि यंत्री, 4 सहायक कृषि यंत्री एवं 2 उपयंत्रियों के पद भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही संचालक कृषि अभियांत्रिकी के पद का भी उन्नयन किया गया है। कृषि के वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक कृषि मशीनों का सर्वाधिक योगदान है। इनसे लागत एवं समय की बचत होती है तथा उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्र जैसे ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, फसल अवशेष प्रबंधन से नरवाई में आग लगाने की समस्या पर नियंत्रण, प्राथमिक प्रसंस्करण की तकनीकों को बढावा देकर कृषकों की आय में वृद्धि करना एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक हो गया है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के विस्तार से प्रदेश में इन क्षेत्रो में तेजी से कार्य किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने की योजना एवं कस्टम हायरिंग योजना प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)